

अनुक्रमणिका

क्र. सं.	टॉपिक का नाम
1.	'मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान' के तहत पौधरोपण का लक्ष्य
2.	भव्या योजना के तहत 5 जिलों का 'मॉडर्न इंडस्ट्रियल हब' के रूप में विकास
3.	'सहकारिता में सहकार' अभियान : राज्य स्तरीय कार्यशाला
4.	न्यूज़ इन शॉर्ट्स 1. चर्चा में प्रतापगढ़ का 'बम्बोरी गाँव' 2. 'चौरसियावास तालाब' बनेगा अजमेर शहर की तीसरी झील 3. नरेश राधानी 'मधुकर' को 'भारत विभूषण सम्मान 2026' 4. सीमा हिंगोनिया की पुस्तक 'सुरक्षा सखी' 5. डूंगरपुर जिले में शिल्पग्राम 6. महिंद्रा वर्ल्ड सिटी लिमिटेड (जयपुर) 7. आबकारी विभाग का 'विशेष निरोधात्मक अभियान' 8. आपणो खेत आपणो खाद अभियान
5.	100वाँ एन-जेन (N-Gen) डाकघर
6.	शहरी परीक्षण केंद्र और एरोसोल वेधशाला
7.	स्वस्थ भारत पोर्टल
8.	कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप, 2026
9.	मायोन ज्वालामुखी
10.	अनुच्छेद-174 (विधानसभा को भंग करना)
11.	ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की दूसरी बैठक, 2026
12.	वियतनाम के राष्ट्रपति की भारत यात्रा
13.	प्रथम अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस (IBCA) शिखर सम्मेलन, 2026
14.	जर्मनियम-मुक्त ड्रोन इमेजिंग तकनीक



राजस्थान परिदृश्य



'मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान' के तहत पौधरोपण का लक्ष्य

चर्चा में क्यों?

- राज्य में हरित आवरण बढ़ाने के उद्देश्य से संचालित मिशन 'हरयाळो राजस्थान' के तहत आगामी मानसून (2026) में सम्पूर्ण राज्य में 10 करोड़ पौधरोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। (स्रोत - DIPR)

मुख्य बिन्दु:

- नोट :** राजस्थान में हरयाळो राजस्थान अभियान, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान और एक पेड़ माँ के नाम अभियान संयुक्त रूप से संचालित किया जा रहा है।
- मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान 'हरयाळो राजस्थान' (एक पेड़ माँ के नाम) के तहत, राजस्थान सरकार ने 2025-26 के बजट में 10 करोड़ पौधे लगाने और उनके संरक्षण का लक्ष्य रखा था। मिशन के अंतर्गत वर्ष 2024 से 2028 तक राज्य में कुल 50 करोड़ पौधरोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- यह पहल प्रधानमंत्री के 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान से प्रेरित है, जो राज्य में हरित आवरण को बढ़ाने के लिए एक मल्टी सेक्टरल कार्यक्रम है।
- राज्य में पौधरोपण कार्यक्रम की प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए तीन-स्तरीय टास्क फोर्स की व्यवस्था है। इसके तहत राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय टास्क फोर्स, जिला स्तर पर जिला कलक्टर तथा उपखण्ड स्तर पर उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में टास्क फोर्स कार्य करेंगी।



अन्य महत्त्वपूर्ण बिन्दु:

- वर्ष 2024 में 'मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान' के अंतर्गत 7 करोड़ पौधरोपण लक्ष्य के विरुद्ध 7.22 करोड़ पौधे लगाए गए। इसी प्रकार मानसून - 2025 में 10 करोड़ लक्ष्य के मुकाबले 11.74 करोड़ से अधिक पौधारोपण कर लक्ष्य से अधिक उपलब्धि प्राप्त की गई।

हरयाळो राजस्थान अभियान के विभागवार आँकड़े:

रैंक	विभाग	कुल रोपे गए पौधे
1	शिक्षा विभाग	40,349,117
2	ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग (MGNREGA, WDSC, Rajeevika)	28,914,629
3	वन विभाग	20,361,250
4	प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	5,673,319
5	स्थानीय स्वशासन विभाग	3,619,814

फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स:

'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान

- शुरुआत :** 5 जून, 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा।
- इस अभियान के तहत लोगों को अपनी माँ के प्रति प्रेम, आदर और सम्मान के प्रतीक के रूप में एक पेड़ लगाने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है और पेड़ों और धरती माँ की रक्षा करने का संकल्प भी लिया जाता है।
- उद्देश्य :** इस अभियान का उद्देश्य भूमि क्षरण की रोकथाम और क्षरित भूमि के पारिस्थितिक पुनर्स्थापन को सुनिश्चित करना है।

भव्या योजना के तहत 5 जिलों का 'मॉडर्न इंडस्ट्रियल हब' के रूप में विकास

चर्चा में क्यों?

- राजस्थान सरकार ने केंद्र सरकार की भव्या (BHAVYA) योजना के तहत 5 जिलों में आधुनिक इंडस्ट्रियल हब (MIH) विकसित करने का प्रस्ताव रखा है।

Ai- Generated image



BHAVYA

Bharat Audyogik Vikas Yojna


Cabinet approves Bharat Audyogik Vikas Yojna (BHAVYA) to develop 100 plug-and-play industrial parks with an allocation of ₹ 33,660 crore

Scheme aims to develop world-class industrial infrastructure, unlocking manufacturing potential and driving India's growth story

Industrial parks from 100 to 1000 acres to be developed with support of up to ₹ 1 crore per acre

BHAVYA to be implemented with states and private sector, under the National Industrial Corridor Development Programme framework

CABINET DECISION
18-03-2025



---4---



मुख्य बिन्दु:

- **5 जिले** : बालोतरा, जयपुर, जोधपुर, कोटा और दौसा।
- **BHAVYA** : भारत औद्योगिक विकास योजना।
- **योजना को मंजूरी** : 18 मार्च, 2026 को केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा।
- **लक्ष्य** : इस योजना के तहत पूरे देश में 100 'प्लग-एंड-प्ले' औद्योगिक पार्क विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है।
- इस योजना के तहत 100 से लेकर 1000 एकड़ तक के औद्योगिक पार्कों को विकास के लिए चुना जाएगा। साथ ही, मुख्य बुनियादी ढांचा, मूल्य-वर्धित बुनियादी ढांचा और सामाजिक बुनियादी ढांचा के लिए प्रति एकड़ ₹1 करोड़ तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- **प्लग-एंड-प्ले मॉडल** : इसका अर्थ है कि उद्योगों के लिए पहले से स्वीकृत भूमि, बिजली, पानी, सड़क और अन्य बुनियादी सुविधाएं तैयार मिलेंगी, जिससे कंपनियां बिना देरी के अपना उत्पादन शुरू कर सकेंगी।
- **उद्देश्य** : विश्व-स्तरीय औद्योगिक बुनियादी ढांचा तैयार करना, मैन्युफैक्चरिंग की संभावनाओं को खोलना।
- **क्रियान्वयन एजेंसी** : नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NICDC), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय।

योजना के तहत लाभार्थी :

- **प्राथमिक लाभार्थी** : विनिर्माण इकाइयां, MSME, स्टार्टअप और ऐसे वैश्विक निवेशक जिन्हें उपयोग के लिए तैयार औद्योगिक बुनियादी ढांचे की आवश्यकता है।
- **द्वितीयक लाभार्थी** : श्रमिक, लॉजिस्टिक्स सेवा प्रदाता, सेवा क्षेत्र के उद्यम और स्थानीय समुदाय।

'सहकारिता में सहकार' अभियान : राज्य स्तरीय कार्यशाला

चर्चा में क्यों?

- 'सहकारिता में सहकार' अभियान के अंतर्गत 8 मई, 2026 को जयपुर में राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला की अध्यक्षता सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक ने की।



मुख्य बिन्दु:

- आयोजक : अपेक्स बैंक, जयपुर और नाबार्ड।
- ज्ञातव्य है कि सहकारिता मंत्रालय देशभर में क्षेत्रीय कार्यशालाओं की एक श्रृंखला आयोजित कर रहा है, ताकि सहकारी क्षेत्र में परिवर्तनकारी सुधारों को गति दी जा सके।

--:6::--

Daily Current Affairs

Date : 08 May, 2026



- इन पहलों का उद्देश्य आधुनिक अनाज भंडारण सुविधाओं को किसानों के निकटतम स्तर तक पहुँचाना, प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) के नेटवर्क को सशक्त एवं विस्तारित करना, सहकारी गतिविधियों में विविधता लाना तथा सहकारी संस्थाओं के सदस्यों एवं लाभार्थियों के कल्याण हेतु 'सहकारिता में सहकार' को बढ़ावा देना है।

फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स (सहकारिता मंत्रालय):

- **स्थापना :** केंद्र सरकार द्वारा 6 जुलाई, 2021 को सहकारिता मंत्रालय के रूप में एक पृथक मंत्रालय की स्थापना की गई।
- **मुख्य उद्देश्य :** "सहकार से समृद्धि" के विजन को साकार करना और देश में सहकारी आंदोलन को मजबूत करना।
- अमित शाह भारत के पहले और वर्तमान सहकारिता मंत्री हैं।

UTKARSH

CIVIL
SERVICES

--7--

✂ न्यूज़ इन शॉर्ट्स ⚡

क्र. सं.	न्यूज़
1.	<p>चर्चा में प्रतापगढ़ का 'बम्बोरी गाँव'</p> <ul style="list-style-type: none">मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 6 मई, 2026 को प्रतापगढ़ के बम्बोरी गाँव में 'ग्राम विकास चौपाल' में भाग लिया तथा रात्रि विश्राम किया।मुख्यमंत्री ने रात्रिकालीन 'ग्राम विकास चौपाल' में ग्रामीणों, महिलाओं, किसानों और युवाओं से सीधा संवाद किया।
2.	<p>'चौरसियावास तालाब' बनेगा अजमेर शहर की तीसरी झील</p> <ul style="list-style-type: none">अजमेर की ऐतिहासिक आनासागर और वरुण सागर (फॉय सागर) के बाद चौरसियावास तालाब को शहर की तीसरी बड़ी झील के रूप में विकसित किया जा रहा है।राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने हाल ही में इस तालाब का अवलोकन कर इसके सौंदर्यीकरण और विकास के लिए ₹5 करोड़ का रोडमैप तैयार किया है।
3.	<p>नरेश राघानी 'मधुकर' को 'भारत विभूषण सम्मान 2026'</p> <ul style="list-style-type: none">हाल ही में, अजमेर के वरिष्ठ पत्रकार और लेखक नरेश राघानी 'मधुकर' को साहित्य और रचनात्मक लेखन में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए 'भारत विभूषण सम्मान 2026' से सम्मानित किया गया।उन्हें यह पुरस्कार उनके द्वारा लिखित चर्चित साइंस फिक्शन उपन्यास 'चिरंजीवी भव' के लिए प्रदान किया गया।यह सम्मान 'इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल रिफॉर्म एंड हायर एजुकेशन ट्रस्ट' (ISRHE) द्वारा नीति आयोग के सहयोग से दिया गया।

4.	<p>सीमा हिंगोनिया की पुस्तक 'सुरक्षा सखी'</p> <ul style="list-style-type: none">■ राजस्थान पुलिस सेवा की अधिकारी सीमा हिंगोनिया द्वारा लिखित पुस्तक 'सुरक्षा सखी' का विमोचन 3 मई, 2026 को जयपुर के झालाना ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट में किया गया।■ यह पुस्तक महिलाओं के सशक्तीकरण और उनकी कानूनी सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शिका (गाइड) है।■ पुस्तक में महिलाओं के आधुनिक दौर के मुद्दों; जैसे - घरेलू हिंसा, साइबर क्राइम, दहेज उत्पीड़न, ट्रिपल तलाक और डायन प्रथा पर 15 कहानियाँ शामिल हैं।
5.	<p>डूंगरपुर जिले में शिल्पग्राम</p> <ul style="list-style-type: none">■ राजस्थान सरकार ने डूंगरपुर जिले के पालवड़ा गाँव में शिल्पग्राम के निर्माण के लिए ₹9 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति जारी की है।■ उद्देश्य : इसका निर्माण उदयपुर के शिल्पग्राम की तर्ज पर स्थानीय हस्तशिल्प और संस्कृति को बढ़ावा देने और पर्यटन को आकर्षित करने के लिए किया जा रहा है।
6.	<p>महिंद्रा वर्ल्ड सिटी लिमिटेड (जयपुर)</p> <ul style="list-style-type: none">■ महिंद्रा वर्ल्ड सिटी लिमिटेड (जयपुर), RIICO एवं महिंद्रा एंड महिंद्रा का संयुक्त उपक्रम है, जहाँ विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ), घरेलू उत्पाद क्षेत्र एवं सामाजिक आधारभूत संरचना क्षेत्र विकसित हैं।■ इसमें रीको की 26 फीसदी भागीदारी है। महिंद्रा वर्ल्ड सिटी लिमिटेड (जयपुर) में 100 से अधिक औद्योगिक इकाइयाँ संचालित हैं, जिनमें करीब 75,000 लोग प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से कार्यरत हैं।

7.	<p>आबकारी विभाग का 'विशेष निरोधात्मक अभियान'</p> <ul style="list-style-type: none">■ राजस्थान आबकारी विभाग द्वारा 1 से 15 मई, 2026 तक प्रदेश भर में अवैध शराब के विरुद्ध 'विशेष निरोधात्मक अभियान' चलाया जा रहा है।■ आबकारी आयुक्त नमित मेहता के निर्देशन में इस अभियान का मुख्य उद्देश्य अवैध मदिरा के निर्माण, भंडारण, परिवहन और बिक्री पर पूर्ण अंकुश लगाना है।
8.	<p>आपणो खेत आपणो खाद अभियान</p> <ul style="list-style-type: none">■ आयोजन अवधि : 6 से 30 अप्रैल, 2026 तक।■ अभियान का मुख्य उद्देश्य : मृदा के स्वास्थ्य में सुधार करना और रासायनिक खादों पर किसानों की निर्भरता को कम करना।■ आयोजक : कृषि विभाग, राजस्थान।



राष्ट्रीय परिदृश्य

100वाँ एन-जेन (N-Gen) डाकघर

चर्चा में क्यों?

- केंद्रीय संचार एवं उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास (DONER) मंत्री ने 6 मई, 2026 को पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय (NEHU), शिलांग में इंडिया पोस्ट के 100वें एन-जेन (N-Gen) डाकघर का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया।



मुख्य बिन्दु:

- परिचय:** इन उन्नत डाकघरों को शैक्षणिक संस्थानों के भीतर स्थापित किया जा रहा है ताकि छात्रों, संकाय सदस्यों और स्थानीय निवासियों को उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप सेवाएं प्रदान की जा सकें।

Daily Current Affairs

Date : 08 May, 2026



■ विशेषताएँ:

1. यह डाकघर पूर्णतः महिलाओं द्वारा संचालित है।
2. बांस एवं पुआल जैसी स्थानीय सामग्री से निर्मित।
3. मेघालय की सांस्कृतिक पहचान को दर्शाने वाला पर्यावरण-अनुकूल मॉडल।
4. शिलांग की "भारत की रॉक राजधानी" पहचान को थीम में शामिल किया गया।

■ N-Gen डाकघर पहल:

1. इंडिया पोस्ट की आधुनिक, युवा-केंद्रित और डिजिटल सेवा नेटवर्क पहल।
2. मुख्यतः विश्वविद्यालयों एवं शैक्षणिक संस्थानों में स्थापित किए जा रहे हैं।
3. उद्देश्य: छात्रों, संकाय सदस्यों और स्थानीय निवासियों को आधुनिक डाक सेवाएँ उपलब्ध कराना।

UTKARSH

CIVIL
SERVICES

-:12:-

शहरी परीक्षण केंद्र और एरोसोल वेधशाला

चर्चा में क्यों?

- पुणे स्थित भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (IITM), 'मिशन मौसम' पहल के तहत कार्यरत है, जिसने चेन्नई के रामपुरम स्थित एसआरएम विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान में अत्याधुनिक शहरी परीक्षण केंद्र और एरोसोल वेधशाला स्थापित की है।



मुख्य बिन्दु:

- यह व्यापक वेधशाला भारत में स्थापित होने वाली अपनी तरह की पहली वेधशाला है।
- उद्घाटन:** 6 मई, 2026 को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव डॉ. एम. रविचंद्रन द्वारा।
- इस केंद्र में लगभग 15 अत्याधुनिक उपकरण हैं जिनकी कीमत 60 करोड़ रुपये से अधिक है। ये उपकरण मौसम के पैटर्न, हवा के प्रवाह, एरोसोल कणों और तापमान में बदलाव सहित लगभग 50 प्रकार के वायुमंडलीय डेटा को ट्रैक करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।

Daily Current Affairs

Date : 08 May, 2026



मिशन मौसम:

- **शुभारंभ:** प्रधानमंत्री ने सितंबर, 2024 में जलवायु मंत्रालय की एक प्रमुख वैज्ञानिक पहल के रूप में भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण के साथ मिशन मौसम का शुभारंभ किया।
- **उद्देश्य:** इस मिशन का उद्देश्य अवलोकन संबंधी बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण, मानसून पूर्वानुमान में सुधार और गंभीर मौसम की तात्कालिक भविष्यवाणी एवं पूर्व चेतावनी के माध्यम से आपदा तैयारियों को बढ़ाना तथा कृषि, जल संसाधन, आपदा प्रबंधन, विमानन और ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों को सहयोग प्रदान करने के लिए जलवायु सेवाओं को मजबूत करना है, जिससे भारत एक "मौसम के लिए तैयार और जलवायु-स्मार्ट राष्ट्र" बन सके।

UTKARSH

CIVIL
SERVICES

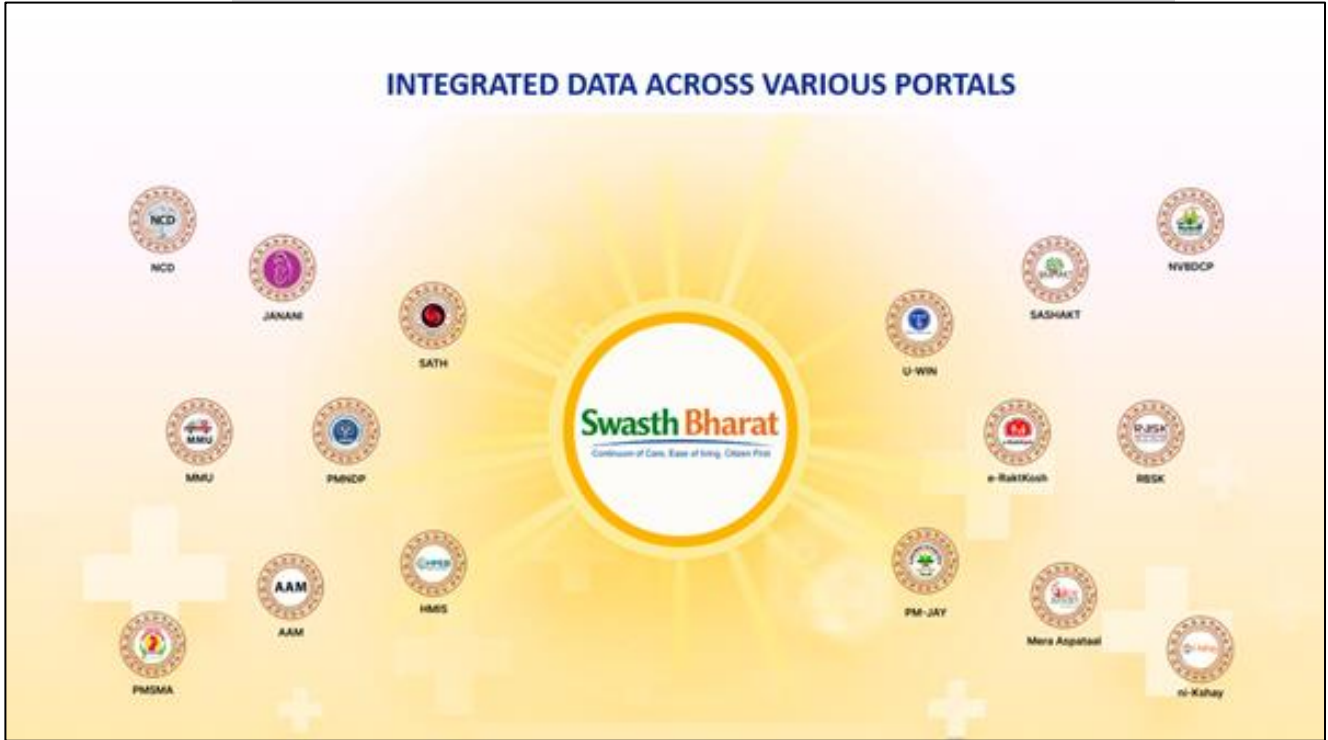
-:14:-

स्वस्थ भारत पोर्टल



चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री द्वारा 'नवाचार एवं समावेशिता' विषय पर 10वें राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन के दौरान स्वास्थ्य भारत पोर्टल का शुभारंभ किया गया।



मुख्य बिन्दु:

- उद्देश्य:** भारत के डिजिटल स्वास्थ्य परिवर्तन को गति देना और खंडित स्वास्थ्य प्रणालियों (Fragmented Health Systems) का एकीकरण करना।
- स्वास्थ्य भारत पोर्टल की दक्षता:**
 - बुनियादी ढांचा: लगभग 20-30 प्रतिशत की कमी
 - डेटा एंट्री में लगने वाला समय: लगभग 20-40 प्रतिशत की कमी
 - मानव संसाधन दोहराव: लगभग 20-40 प्रतिशत की कमी
 - निर्णय लेने की गति: बढ़ेगी

कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप, 2026



मुख्य बिन्दु:

- **आयोजन:** 27 जुलाई से 2 अगस्त, 2026 तक त्यागराज स्टेडियम, दिल्ली में कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप, 2026 का आयोजन किया जाएगा।
- **भागीदार:** इसमें 35 से अधिक देशों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे।
- **आयोजक:** यह प्रतियोगिता दिल्ली सरकार और टेबल टेनिस महासंघ द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की जाएगी।

भूगोल एवं भू-विज्ञान

मायोन ज्वालामुखी



📢 चर्चा में क्यों?

- 3 मई, 2026 को फिलीपींस के अल्बे प्रांत में स्थित मायोन ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, जिसके बाद अधिकारियों ने पांच चरणों वाले पैमाने पर अलर्ट को लेवल 3 तक बढ़ा दिया है।

📌 मुख्य बिन्दु:

- **परिचय:** यह एक उत्कृष्ट स्ट्रेटोवोलकानो (मिश्रित ज्वालामुखी) है, जिसकी ऊपरी ढलानें खड़ी हैं और शिखर पर एक छोटा सा गड्ढा है।
- **उपनाम:** यह अपनी अत्यधिक सममित संरचना के कारण अपने "परिपूर्ण शंकु" आकार के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है।
- **अवस्थिति:** लूज़ोन द्वीप, अल्बे प्रांत, फिलीपींस।
- **विस्फोटक पदार्थ (स्ट्रोम्बोलियन विस्फोट):** लावा प्रवाह, पायरोक्लास्टिक घनत्व धाराएं (PDC) और लाहार (कीचड़ प्रवाह)।
- **उत्पत्ति:** यह प्रशांत अग्नि वलय का हिस्सा है और फिलीपीन सागर प्लेट के फिलीपीन मोबाइल बेल्ट के नीचे धंसने से बना है।
- यहाँ मायोन ज्वालामुखी प्राकृतिक पार्क अवस्थित हैं।
- **ऐतिहासिक विस्फोट:** मायोन ज्वालामुखी में विस्फोट की सबसे विनाशकारी घटना फरवरी, 1814 में हुई थी, जिसने कागसावा शहर को राख और लावा के नीचे दबा दिया था।

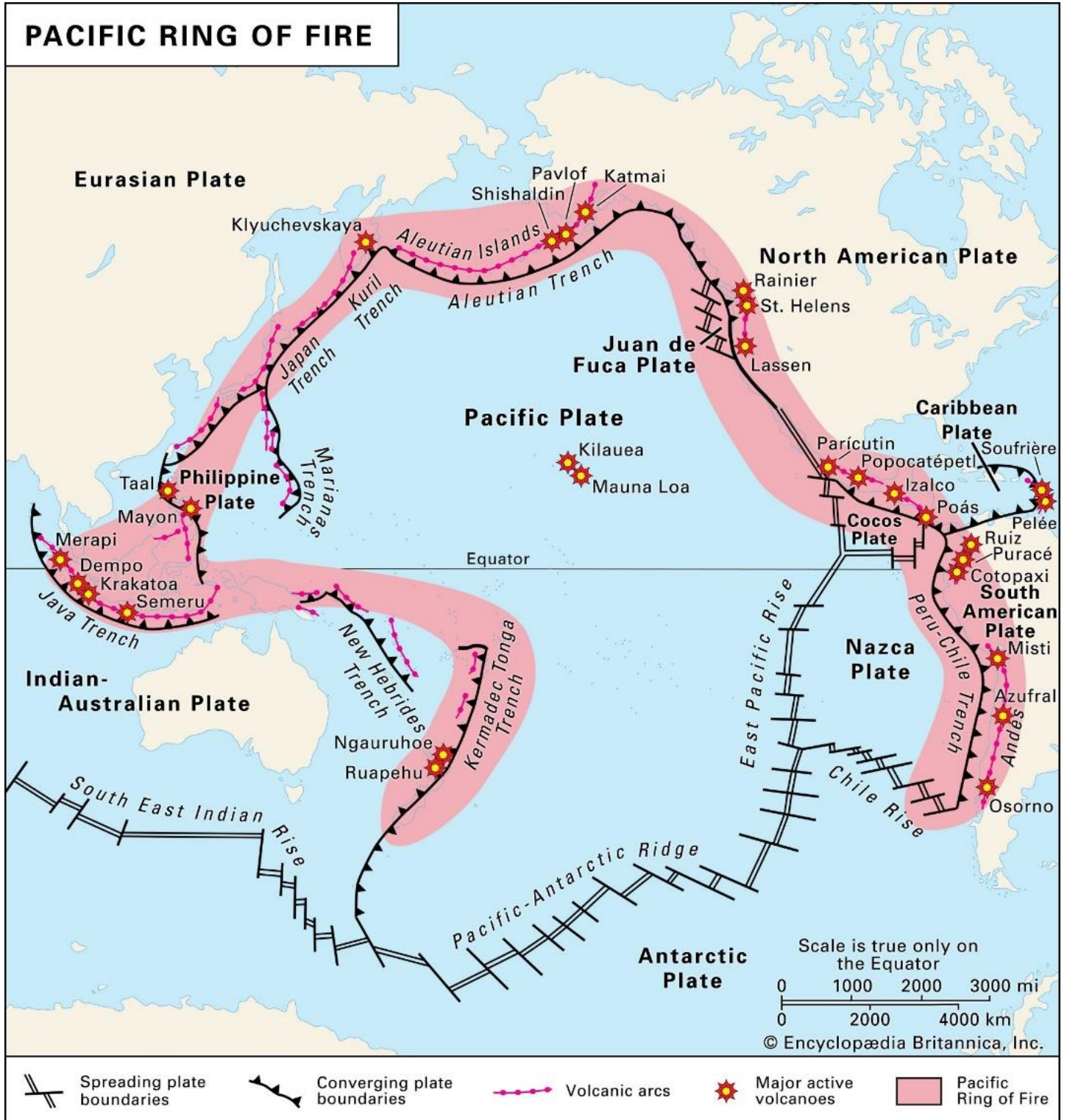
Daily Current Affairs

Date : 08 May, 2026



अन्य महत्त्वपूर्ण बिन्दु:

प्रशांत अग्नि वलय:



--:19:--

Daily Current Affairs

Date : 08 May, 2026



- **परिचय:** प्रशांत महासागर का अग्नि वलय (परि-प्रशांत बेल्ट) प्रशांत महासागर बेसिन में स्थित एक विशाल, घोड़े की नाल के आकार का क्षेत्र है, जो लगातार भूकंपों और ज्वालामुखी विस्फोटों से प्रभावित होता है।
- **क्षेत्रफल:** लगभग 40,000 किलोमीटर।
- **अवस्थिति:** रिंग ऑफ फायर, दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी सिरे से शुरू होकर एंडीज पर्वतमाला से होते हुए मध्य अमेरिका, अमेरिका और कनाडा के पश्चिमी तट से गुजरते हुए अलास्का में एल्यूशियन द्वीप समूह को पार करते हुए जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, पापुआ न्यू गिनी से होते हुए न्यूजीलैंड के पास समाप्त होता है।
- **विशेषता:** इस वलय में विश्व के लगभग 75% सक्रिय और निष्क्रिय ज्वालामुखी स्थित हैं।
- **कारण:** रिंग ऑफ फायर में होने वाली गतिविधि प्लेट टेक्टोनिक्स, विशेष रूप से सबडक्शन ज़ोन के कारण होती है, जहाँ एक महासागरीय प्लेट एक महाद्वीपीय प्लेट के नीचे खिसक जाती है।

--:20:--

भारतीय शासन एवं राजव्यवस्था

अनुच्छेद-174 (विधानसभा को भंग करना)

चर्चा में क्यों?

- 7 मई, 2026 को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आर.एन. रवि ने विधानसभा को भंग कर दिया है। यह निर्णय राज्य में 2026 के विधानसभा चुनाव के परिणामों के बाद लिया गया।

West Bengal



--:21:--



मुख्य बिन्दु:

- **संवैधानिक प्रावधान: अनुच्छेद-174, भारत का संविधान 1950**
 - (1) राज्य के विधानमंडल के सदन को प्रत्येक वर्ष कम से कम दो बार बैठक के लिए बुलाया जाएगा, और एक सत्र में उनकी पिछली बैठक और अगले सत्र में उनकी पहली बैठक के लिए निर्धारित तिथि के बीच छह महीने का अंतराल नहीं होगा।
 - (2) खंड (1) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, राज्यपाल समय-समय पर-
 - (क) सदन या दोनों सदनों को ऐसे समय और स्थान पर बैठक के लिए बुलाना जैसा वह उचित समझे;
 - (ख) सदन या सदनों का सत्र स्थगित करना;
 - (ग) विधान सभा भंग करना।
- **कारण:** चुनाव नतीजों के बाद, पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा इस्तीफा देने से इनकार करने के बाद यह कदम उठाया गया।

अनुच्छेद-174 से संबंधित प्रमुख वाद:

 1. **नबम रेबिया और बामंग फेलिक्स बनाम उप अध्यक्ष, अरुणाचल प्रदेश (वर्ष 2016):** सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद-174(1) के तहत राज्यपाल के विवेक का प्रयोग संवैधानिक मानदंडों और मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार किया जाना चाहिए।
 2. **पंजाब राज्य बनाम सत्य पाल डांग (वर्ष 1969):** न्यायालय ने विधान सभा को भंग करने की राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति को बरकरार रखा, बशर्ते कि ऐसी कार्रवाई संवैधानिक ढाँचे के भीतर रहे।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद-174 का महत्त्व:

 1. **नियमित विधायी सत्रों को सुनिश्चित करना:** राज्य विधानमंडल के दो सत्रों के बीच छह महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए।
 2. **कार्यपालिका और विधायिका की शक्तियों में संतुलन:** यद्यपि राज्यपाल को विधायिका को बुलाने, स्थगित करने और भंग करने का अधिकार है, फिर भी इन शक्तियों का प्रयोग सामान्यतः मंत्रिपरिषद की सलाह पर किया जाता है।
 3. **लोकतांत्रिक पुनरुद्धार:** विधान सभा का विघटन नए चुनाव कराने में सक्षम बनाता है, जिससे मतदाताओं को नए प्रतिनिधियों को चुनने का अवसर मिलता है।

अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य

ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की दूसरी बैठक, 2026

चर्चा में क्यों?

- 7 मई, 2026 को ब्रिक्स में भारत की अध्यक्षता में आयोजित ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह (EWG) की दूसरी बैठक तिरुवनंतपुरम में सफलतापूर्वक पूरी हुई।



मुख्य बिन्दु:

- आयोजन:** 6-7 मई, 2026 तक तिरुवनंतपुरम, केरल।
- यह बैठक भारत की 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता की विषयवस्तु - तन्यकशीलता, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण से प्रेरित थी।
- उद्देश्य:** डिजिटल प्रौद्योगिकी, सामाजिक सुरक्षा एवं महिलाओं की कार्यबल भागीदारी में सहयोग बढ़ाना, कौशल विकास एवं रोजगार क्षमता को सुदृढ़ करना।

--:23:--

■ चर्चा के 4 प्रमुख विषयगत क्षेत्र:

1. सामाजिक सुरक्षा एवं औपचारिकीकरण को बढ़ावा।
2. महिला श्रम बल भागीदारी (FLFPR) बढ़ाना।
3. रोजगार क्षमता एवं कौशल विकास सहयोग मजबूत करना।
4. गिग एवं प्लेटफॉर्म श्रमिकों सहित सभी श्रमिकों के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग।

- ## ■ सांस्कृतिक आयाम:
- प्रतिनिधियों के लिए केरल की सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ आयोजित की गईं, जिनमें: भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, कलरीपयट्ट, मयूर नृत्यम, मार्गमकाली, ओप्पना आदि शामिल रहे।

प्रमुख निष्कर्ष:

1. सभी प्रकार के कार्यों में सामाजिक सुरक्षा कवरेज बढ़ाने पर सहमति।
 2. महिलाओं की कार्यबल भागीदारी को समावेशी विकास का महत्वपूर्ण सूचक माना गया।
 3. आजीवन शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल-से-नौकरी मिलान पर जोर।
 4. भारत द्वारा ILO सहयोग से किए जा रहे व्यवसायों के संदर्भ वर्गीकरण अध्ययन।
 5. गिग एवं अनौपचारिक श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता पर बल।
 6. डिजिटलीकरण को श्रम बाजार परिवर्तन का प्रमुख माध्यम माना गया।
- ## ■ ब्रिक्स के सदस्य देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, इंडोनेशिया और संयुक्त अरब अमीरात हैं।

वियतनाम के राष्ट्रपति की भारत यात्रा

चर्चा में क्यों?

- समाजवादी गणराज्य वियतनाम के राष्ट्रपति और 'वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी' की केंद्रीय समिति के महासचिव तो लाम 5 से 7 मई, 2026 तक भारत की तीन दिवसीय राजकीय यात्रा सम्पन्न की।



Daily Current Affairs

Date : 08 May, 2026



मुख्य बिन्दु:

- अप्रैल, 2026 में वियतनाम के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद राष्ट्रपति तो लाम की यह भारत की पहली राजकीय यात्रा थी।
- राष्ट्रपति तो लाम की यह यात्रा ऐसे विशेष अवसर पर हो रही है, जब दोनों देश वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री मोदी की वियतनाम यात्रा के दौरान हुए व्यापक रणनीतिक साझेदारी के समझौते की 10वीं वर्षगाँठ मना रहे हैं।

परिणाम:

घोषणाएं:

क्रमांक	शीर्षक
1.	द्विपक्षीय संबंधों को उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाना।
2.	वर्ष 2030 तक 25 अरब अमेरिकी डॉलर का नया व्यापार लक्ष्य।
3.	वियतनाम इंडो पैसिफिक ओशनस इनिशिएटिव (IPOI) में शामिल हो रहा है।
4.	भारतीय अंगूरों का वियतनाम को और वियतनामी ड्यूरियन का भारत को निर्यात करने की घोषणा।
5.	माई सोन में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल पर स्थल व्याख्या केंद्र की स्थापना।

- **समझौतों की सूची:** 13 रणनीतिक समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर।

शीर्षक	संक्षिप्त विवरण
IREL (इंडिया) लिमिटेड और वियतनाम के इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी ऑफ रेडियोएक्टिव एंड रेयर एलिमेंट्स (ITRRE) के बीच पारस्परिक सहयोग पर समझौता ज्ञापन	यह समझौता ज्ञापन दुर्लभ खनिज तत्वों और अन्य उन्नत प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग का विस्तार करने के लिए दोनों पक्षों की लंबे समय से चली आ रही प्रतिबद्धता को औपचारिक रूप देता है।

--:26:--

Daily Current Affairs

Date : 08 May, 2026



भारत के संस्कृति मंत्रालय और वियतनाम के संस्कृति, खेल और पर्यटन मंत्रालय के बीच वर्ष 2026-30 के लिए सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम	भारत और वियतनाम के बीच वर्ष 1976 में एक सांस्कृतिक समझौता हुआ था। इस समझौते के अंतर्गत की जाने वाली विशिष्ट गतिविधियों और आदान-प्रदान पर पाँच साल (2026-2030) की अवधि के लिए वैध सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम (CEP) के ढाँचे के भीतर सहमति बनी है।
बृहन्मुंबई नगर निगम, मुंबई और हो ची मिन्ह सिटी पीपुल्स कमेटी के बीच मैत्री और सहयोग स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन।	इस समझौते का उद्देश्य दोनों महानगरों को शहरी प्रबंधन और आर्थिक विकास में विशेषज्ञता साझा करने में सक्षम बनाने के लिए एक औपचारिक ढाँचा स्थापित करना है।
आईसीसीआर और दा नांग विश्वविद्यालय के विज्ञान और शिक्षा विश्वविद्यालय के बीच ICCR चेयर ऑफ इंडिया स्टडीज की स्थापना के संबंध में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।	इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत वियतनाम के दा नांग विश्वविद्यालय में ICCR चेयर की स्थापना की गई है।
नालंदा विश्वविद्यालय, राजगीर और हो ची मिन्ह राष्ट्रीय राजनीति अकादमी (HCMA), हनोई के बीच समझौता ज्ञापन।	यह समझौता ज्ञापन वियतनाम में क्षमता विकास और प्रशिक्षण को सुविधाजनक बनाने के लिए भारत की दीर्घकालिक पहलों को मजबूत करता है।
एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (एनआईपीएल) और नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ वियतनाम (एनएपीएएस) के बीच समझौता ज्ञापन।	इस समझौता ज्ञापन से भारत की एनआईपीएल और वियतनाम की एनएपीएएस के बीच सीमा पार QR कोड की अंतरसंचालनीयता पर संस्थागत संबंध स्थापित होगा, ताकि भुगतान को सक्षम बनाया जा सके।

--:27:--

संस्कृति मंत्रालय के ज्ञान भारतम और सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी विश्वविद्यालय, वियतनाम राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, हो ची मिन्ह सिटी (USSH, VNUHCM) के बीच चाम पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण पर समझौता ज्ञापन।

इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत एनएमएम, इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केंद्र और USSH, VNUHCM के बीच वियतनाम में संरक्षित भारतीय मूल की चाम पांडुलिपियों के सर्वेक्षण, प्रलेखन, संरक्षण, डिजिटलीकरण और ऑनलाइन प्रसार के लिए संस्थागत संबंध स्थापित किए गए हैं।

अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु:

भारत के लिए वियतनाम का महत्त्व:

- **एक्ट ईस्ट पॉलिसी में महत्वपूर्ण साझेदार:** यह भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इंडो-पैसिफिक विजन तथा क्षेत्रीय सहयोग रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
- **सामरिक एवं भौगोलिक महत्त्व:** यह दक्षिण चीन सागर के प्रमुख समुद्री व्यापार मार्गों के निकट स्थित है, जिससे क्षेत्र में सुरक्षित एवं निर्बाध व्यापार सुनिश्चित करने में सहायता मिलती है।
- **चीन के प्रभाव का संतुलन:** भारत और वियतनाम दोनों दक्षिण चीन सागर में नौवहन की स्वतंत्रता तथा नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था का समर्थन करते हैं।
- **दोनों देश वर्ष 1982 के संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन (UNCLOS) के सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्ध हैं।**
- **आपूर्ति श्रृंखला विविधीकरण:** दुर्लभ खनिजों एवं औद्योगिक आयात के क्षेत्र में सहयोग से भारत की विनिर्माण क्षमता को मजबूती मिलती है।
- **ऊर्जा सुरक्षा:** भारतीय कंपनियों ने दक्षिण चीन सागर में वियतनामी जलक्षेत्र में तेल और गैस अन्वेषण परियोजनाओं में निवेश किया है, जो हाइड्रोकार्बन भंडार से अत्यंत समृद्ध है।

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

प्रथम अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस (IBCA) शिखर सम्मेलन, 2026

चर्चा में क्यों?

- केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री ने नई दिल्ली में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस (IBCA) शिखर सम्मेलन, 2026 के लिए आधिकारिक वेबसाइट और लोगो का शुभारंभ किया।



मुख्य बिन्दु:

- मेजबानी: भारत (आयोजक: केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय)
- शिखर सम्मेलन का आयोजन: 01-02 जून, 2026 को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा।

--:29:--

Daily Current Affairs

Date : 08 May, 2026



- वर्ष 2026 में शिखर सम्मेलन का विषय/थीम: 'बड़ी बिल्लियों को बचाएँ, मानवता को बचाएँ, पारिस्थितिकी तंत्र को बचाएँ'।
- भागीदारी: पूरी दुनिया से 400 से अधिक संरक्षणवादी, नीति निर्माता, वैज्ञानिक, बहुपक्षीय एजेंसियाँ, वित्तीय संस्थान, कॉर्पोरेट नेता और समुदाय के प्रतिनिधियों को एकत्रित करेगा।
- सम्मेलन का लोगो: लोगो सामंजस्य, संतुलन और परस्पर जुड़े पारिस्थितिक तंत्र को दर्शाता है। लोगो के केंद्र में सात बड़ी बिल्ली प्रजातियों को दर्शाया गया है, जो एकता एवं साझा जिम्मेदारी का प्रतीक हैं और इसके चारों ओर कमल-प्रेरित एक डिजाइन है जो प्रकृति के पांच तत्वों का प्रतिनिधित्व करता है।



- सम्मेलन की वेबसाइट: यह आउटरीच, जुड़ाव एवं सूचना साझा करने के लिए एक समर्पित वैश्विक मंच के रूप में कार्य करेगी। इस पर आधिकारिक IBCA समिट, 2026 का लोगो फिल्म भी प्रदर्शित की जाएगी।
- परिणाम: शिखर सम्मेलन का एक प्रमुख परिणाम बड़ी बिल्लियों के संरक्षण पर 'दिल्ली घोषणा' नामक पहली वैश्विक संकल्प की स्वीकृति होगी।

--:30:--

अन्य महत्त्वपूर्ण बिन्दु:

अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस (IBCA):

- **परिचय:** IBCA एक बहु-देशीय, बहु-एजेंसी गठबंधन है, जिसमें 95 विशाल बिल्ली-आश्रय वाले देश, विशाल बिल्ली संरक्षण में रुचि रखने वाले गैर-आश्रय वाले देश, संरक्षण भागीदार, विशाल बिल्ली अनुसंधान में लगे वैज्ञानिक संगठन, साथ ही विशाल बिल्ली संरक्षण प्रयासों का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध व्यावसायिक समूह और निगम शामिल हैं।
- **IBCA की आवश्यकता:** आवास की क्षति, अवैध शिकार, जलवायु परिवर्तन और मानव-वन्यजीव संघर्ष के कारण बिग कैट खतरे में हैं।
- **स्थापना:** भारत की बाघ परियोजना के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 9 अप्रैल, 2023 को कर्नाटक के मैसूरु में आयोजित एक भव्य अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में, भारतीय प्रधानमंत्री ने बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा सहित सात बड़ी बिल्लियों के वैश्विक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस (IBCA) की स्थापना की।
- **मुख्यालय और सचिवालय:** भारत गणराज्य के निर्णय के अनुसरण में, मंत्रिमंडल ने 12 मार्च, 2024 को भारत में मुख्यालय के साथ IBCA की स्थापना को मंजूरी दी।
- **उद्देश्य:** विशाल बिल्लियों के संरक्षण क्षेत्र वाले देशों, संरक्षण में रुचि रखने वाले गैर-विभागीय देशों, संरक्षण साझेदारों, वैज्ञानिक संगठनों और विशाल बिल्लियों के संरक्षण में सहयोग करने के इच्छुक व्यावसायिक समूहों को एकजुट करना।
- **कार्यान्वयन:** IBCA की स्थापना पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) के माध्यम से की गई थी।
- **अध्यक्ष:** पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव।
- **सचिवालय महानिदेशक:** डॉ. एसपी यादव (प्रथम महानिदेशक)।

Daily Current Affairs

Date : 08 May, 2026



- **पर्यवेक्षक देश:** कजाखस्तान, नामिबिया और थाईलैंड
- **सदस्य देश:** अंगोला, आर्मीनिया, भूटान, कंबोडिया, इरिट्रिया, इथियोपिया, एस्वातिनी, गिनी, ग्वाटेमाला, भारत, लाइबेरिया, मलेशिया, मंगोलिया, म्यांमार, नाइजर, निकारागुआ, नेपाल, परागुआ, रूस, रवांडा, श्रीलंका, सोमालिया, दक्षिण सूडान और सूरीनाम।
- **नोट:** संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश इसकी सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं, जिनमें वे रेंज देश भी शामिल हैं, जहाँ ये प्रजातियाँ मूल रूप से पाई जाती हैं तथा वे नॉन-रेंज देश भी शामिल हैं जो बिग कैट के संरक्षण में सहयोग करने में रुचि रखते हैं।
- **भागीदार संगठन:** प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ (स्विट्ज़रलैंड), अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ ट्रस्ट (किर्गिज़स्तान), ग्लोबल टाइगर फोरम (भारत), अमूर टाइगर सेंटर (रूस), विश्व वन्यजीव कोष अंतर्राष्ट्रीय (स्विट्ज़रलैंड), विश्व सीमा शुल्क संगठन (बेल्जियम), मोबियस फाउंडेशन (भारत), चीता संरक्षण कोष (नामिबिया), सतत हरित अर्थव्यवस्था केंद्र (भारत),
- संयुक्त राष्ट्र का खाद्य एवं कृषि संगठन (इटली), संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन (स्पेन) और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (अमेरिका)।
- **संरक्षण:** सात बड़ी बिल्लियों का संरक्षण; बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा।
- **वित्तपोषण:** भारत ने IBCA को 150 करोड़ रुपए (2023-2028) की सहायता देने का संकल्प लिया है।
- **भारत में बिग कैट के संरक्षण के प्रयास:** एशियाई प्रोजेक्ट लायन, प्रोजेक्ट हिम तेंदुआ, प्रोजेक्ट चीता, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL), प्रोजेक्ट टाइगर

--:32:--

Daily Current Affairs

Date : 08 May, 2026

UTKARSH
CLASSES

CIVIL
SERVICES

बड़ी बिल्लियों की संरक्षण स्थिति

प्रजातियाँ	वैज्ञानिक नाम	IUCN लाल सूची	स्थल	भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972
बाघ	पैंथेरा टाइग्रिस	संकटग्रस्त	परिशिष्ट-1	अनुसूची-1
शेर	पैंथेरा लियो	असुरक्षित	परिशिष्ट-1	अनुसूची-1
तेंदुए	पैंथेरा पार्डस	असुरक्षित	परिशिष्ट-1	अनुसूची-1
हिम तेंदुए	पैंथेरा अन्सिया	असुरक्षित	परिशिष्ट-1	अनुसूची-1
प्यूमा	प्यूमा कॉनकलर	कम चिंतनीय	परिशिष्ट-11 (P. c. कोस्टारिकेंसिस और कूगर: परिशिष्ट-1)	NA
जगुआर	पैंथेरा ओंका	निकट संकटग्रस्त	परिशिष्ट-1	NA
चीता	एसिनोनिक्स जुबेटस	असुरक्षित	परिशिष्ट-1	अनुसूची-1

--:33:--

⌚ विज्ञान प्रौद्योगिकी 🌡️

जर्मनियम-मुक्त ड्रोन इमेजिंग तकनीक

📢 चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, हैदराबाद स्थित स्टार्टअप ईऑनस्पेसलेब्स ने ड्रोन के लिए भारत का पहला जर्मनियम-मुक्त थर्मल इमेजिंग पेलोड 'Lumira_E40I50' (लुमिरा) लॉन्च किया है।



📌 मुख्य बिन्दु:

- **जर्मनियम-मुक्त ड्रोन इमेजिंग तकनीक का परिचय:** यह एक स्वदेशी इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल और इन्फ्रारेड (ईओ/आईआर) इमेजिंग सिस्टम है जो पारंपरिक जर्मनियम-आधारित लेंसों को घरेलू विकल्प से प्रतिस्थापित करता है। परंपरागत रूप से, सैन्य-श्रेणी के थर्मल कैमरे ऊष्मा विकिरण संचारित करने के लिए जर्मनियम पर निर्भर करते हैं; हालांकि, यह नया सिस्टम दुर्लभ खनिज के बिना समान प्रदर्शन प्राप्त करने के लिए चैल्कोजेनाइड ग्लास का उपयोग करता है।

- **विकास:** रक्षा प्रौद्योगिकी स्टार्टअप ईऑनस्पेसलैब्स, हैदराबाद।
- **उद्देश्य:** प्राथमिक लक्ष्य वैश्विक जर्मनियम आपूर्ति पर प्रभुत्व रखने वाले चीन पर भारत की निर्भरता को कम करके रणनीतिक स्वायत्तता प्राप्त करना है।

प्रमुख विशेषताएँ:

1. **तकनीकी सफलता:** पारंपरिक जर्मनियम लेंस के बजाय, यह थर्मल कैमरा चाल्कोजेनाइड ग्लास का उपयोग करता है, जो उच्च प्रदर्शन प्रदान करता है।
2. **लंबी दूरी की निगरानी:** यह सिस्टम 2 किमी तक मनुष्यों और 8 किमी तक वाहनों की पहचान करने में सक्षम है, जो इसे खुफिया (ISR) मिशनों के लिए आदर्श बनाता है।
3. **ऑप्टिकल ज़ूम (ऑनबोर्ड AI):** उच्च परिशुद्धता निगरानी के लिए 40x ऑप्टिकल ज़ूम से सुसज्जित।
4. **पर्यावरणीय लचीलापन:** इसे -20°C से $+55^{\circ}\text{C}$ तक के अत्यधिक तापमान में काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
5. **वजन और सुवाह्यता:** इसका पेलोड हल्का है (800 ग्राम से 2.2 किलोग्राम तक), जिससे यह कॉम्पैक्ट ड्रोन, एयरोस्टेट और ईवीटीओएल प्लेटफॉर्म के साथ संगत है।

अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु:

- संजय कुमार, पुनीत बडेका और मनोज कुमार गद्दाम द्वारा वर्ष 2021 में स्थापित यह कंपनी ड्रोन, उपग्रहों और निगरानी प्लेटफार्मों के लिए इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल और इन्फ्रारेड (EO/IR) पेलोड पर ध्यान केंद्रित करती है।
- **जर्मनियम समस्या क्यों बन सकता है?** : जर्मनियम महंगा है, पूरी तरह से आयात किया जाता है, और वैश्विक आपूर्ति में व्यवधान के अधीन है।